

परिणामी बजट वर्ष 2017-18

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्राप्तधान 2017-18	क्वाटिफायरेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
1	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु कार्यक्रमों को संचालित कर हितग्राहियों को क्रियान्वयन हेतु	400000	निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वित होंगे :- <ol style="list-style-type: none">सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकासकौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारस्व-स्वरोजगार कार्यक्रमप्रशिक्षण एवं क्षमता विकासशहरी पथ विकेताओं को सहायताशहरी वेचारों के लिए आश्रय की योजनाप्रशासनिक एवं अन्य व्ययसूचना सम्प्रेषण मद	
2	स्मार्ट सिटी	राजधानी रायपुर का स्मार्ट सिटी के मापदण्ड अनुरूप विकसित करना।	2000000	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रो फिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास, जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है।	
3	स्वच्छ भारत मिशन	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है।	3160000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है।	
4	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना “सबके लिए आवास योजना” के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये क्रियान्वयन होंगे:-	2000000		

परिणामी बजट वर्ष 2017-18

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, नगर प्रशासन, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2017-18	क्वाटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
		1. झुग्गी बस्ती पुनर्विकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण		वर्ष 2015-2022 तक सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्राय सहायता का प्रावधान है। प्रथम श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए 04 चरणों में क्रियान्वयन किया जाना है।	
5	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए बर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।	2100000	राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया।	
6	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	94100	नगरीय निकायों में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था	
7	नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन	निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षित तथा निजता और प्रतिष्ठा के अनुरूप सर्व सुलभ सार्वजनिक प्रसाधन	50000	168 के नगरीय निकाय में महिला सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण कार्य हेतु।	
8	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है।	100000	168 निकायों में आवश्यकतानुसार वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	
9	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय	615000		

परिणामी बजट वर्ष 2017-18

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, नगर प्रशासन, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2017-18	क्वाटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
		निकायों को कार्ययोजना अनुसार आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत निकायों को पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय साफ सफाई एवं सामुदायिक भवन आदि के लिए अनुदान		168 नगरीय निकायों के लिए निम्नांकित कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. ठोस अवशिष्ट सामग्री कथ प्रबंधन	
10	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चालू होने से राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका, कौशल उन्नयन तथा जमीनी स्तर के संस्थाओं के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।	50000	राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका तथा जमीनी स्तर के संस्थाओं के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।	
11	विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनुदान	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण के अनुपात में अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।	150000	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है ।	
12	विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु अनुदान के अनुपात में ऋण स्वीकृत किया जाता है ।	500000		

परिणामी बजट वर्ष 2017-18

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2017-18	क्वाटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
13	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1300	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है।	dksbz
14	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	3685000	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निमानकित कार्य प्रमुखतः से किया जाना है। 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लाइ ओवर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किंग स्थल निर्माण 4. पशु वंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोर्ट्स काम्पलेक्स 7. बिलासपुर/रायपुर में फ्लाइ ओवर निर्माण 8. नगरीय निकायों में हाईटक बस स्टैण्ड का निर्माण 9. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कामकाजी महीला छात्रावास का निर्माण	
15	लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)	नगर निगम कोरबा एवं भिलाई चरौदा की जलार्बद्धन योजना	10000	नगर निगम कोरबा तथा भिलाई-चरौदा की परियोजनाओं हेतु।	

परिणामी बजट वर्ष 2017-18

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम

उद्देश्य/परिणाम

बजट प्रावधान

2017-18

क्वाटिफायेबल डिलीवरेबल्स

टिप्पणियाँ
